Publication	**The Pioneer**	**Language**	English
Edition	New Delhi	**Journalist**	Bureau
Date	24/07/2025	**Page no**	2
CCM	57.72		

Shah to unveil National Cooperative Policy 2025 on July 24

Shah to unveil National Cooperative Policy 2025 on July 24

PIONEER NEWS SERVICE
New Delhi

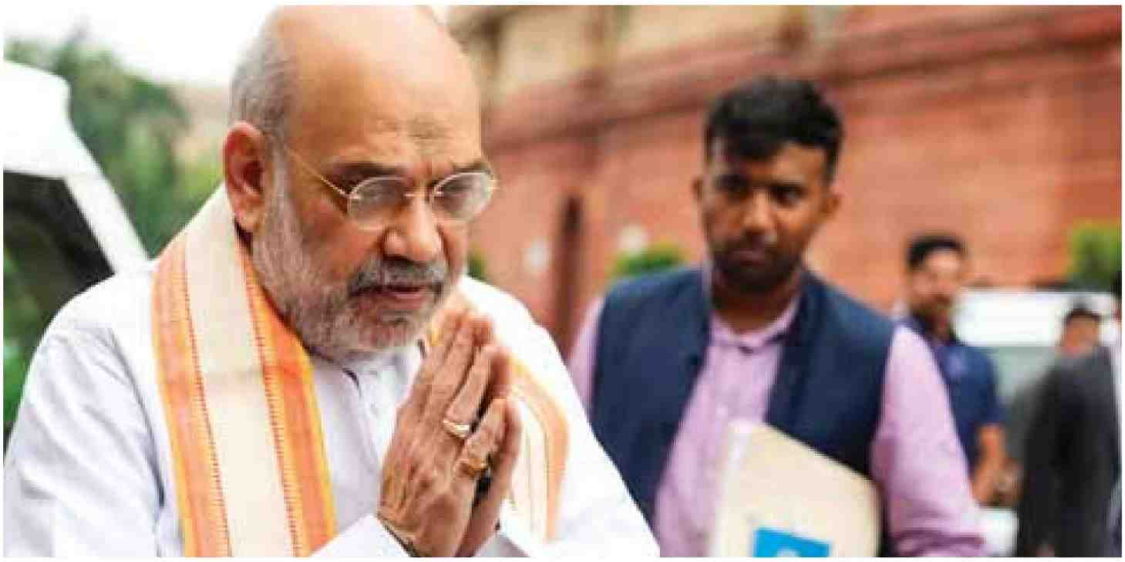

Union Home Minister Amit Shah during the Monsoon Session of Parliament in New Delhi on Wednesday PTI

Union Home Minister and Minister of Cooperative Amit Shah will announce the National Cooperative Policy 2025 at Atal Akshay Urja Bhawan, New Delhi on July 24. The new policy will target to revive and modernise the cooperative sector. This will replace the first National Cooperative Policy issued in 2002.

Members of the drafting committee of the National Cooperative Policy, Chairmen and Managing Directors of all National Cooperative Unions, senior officials of the Ministry, senior officials of National Cooperative Development Corporation (NCDC), National Council of Cooperative Training (NCCT) and Vaikunth Mehta National Institute of Cooperative Management (VAMNICOM) will be present on the occasion.

The new cooperative policy will prove to be a milestone in the cooperative movement of India for the next two decades from 2025-45. The new cooperative policy 2025 aims to revive and modernize the cooperative sector as well as realize the vision of prosperity through cooperation by creating a roadmap at the grassroots level.

Earlier in the year 2002, the country's first National Cooperative Policy was issued, which gave a basic framework for better management of the economic activities of cooperative institutions.

In the last 20 years, many major changes have taken place in the society, country and the world due to globalisation and technological advancement. Keeping these changes in mind, it became necessary to formulate a new policy, so that cooperative institutions can be made more active and useful in the current economic scenario and the role of the cooperative sector can be strengthened in achieving the goal of "Viksit Bharat 2047".

The objective of the National Cooperative Policy is to make cooperative institutions inclusive, manage them professionally, prepare them for the future and be able to create large scale employment and livelihood opportunities especially in rural India.

"A 48-member national-level committee headed by former Union Minister Suresh Prabhakar Prabhu has prepared the new National Cooperative Policy. This committee included members from national/State cooperative federations, cooperative societies of all levels and sectors, representatives of the concerned Central and State Government Ministry and academicians," according to an official statement.

Downloaded from
SAMVAD

Publication	**Hari Bhoomi**	**Language**	Hindi
Edition	New Delhi	**Journalist**	The Edit Desk
Date	24/07/2025	**Page no**	8
CCM	125.11		

The coming 100 years of cooperation

आने वाले 100 साल सहकारिता के

लक्ष्य
प्रो. कन्हैया त्रिपाठी

अमित शाह ने 'सहकार एवं रोजगार उत्सव' में युवाओं से कहा कि मोदी सरकार ने 11 साल के कार्यकाल में 60 करोड़ गरीबों के लिए घर, शौचालय, बिजली, गैस, पांच किलो मुफ्त अनाज और पांच लाख रुपये तक के इलाज और मुफ्त दवाइयों की व्यवस्था की। हर गांव, गरीब और किसान तक सहकारिता को पहुंचाने के लक्ष्य के साथ केन्द्र सरकार में एक स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय स्थापित किया। आज 98 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में सहकारिता की सक्रिय भूमिका है। आगामी 100 साल सहकारिता के होंगे। अतीत के सहकारिता के आन्दोलनों से अब तक के आकलन के साथ गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय सहकारिता की पहुंच को रेखांकित किया।

भारत के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का मानना है कि अतीत आपने देखा, अब भविष्य की ओर देखो। पूरब से आने वाली सूरज की रश्मियां आपको ताजगी से भर देंगी। इनमें सहकारिता की ओज है। सहकारिता की ओज से हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में उजाला पसरने जा रहा है। अमित शाह का उत्साहवर्धन निश्चय ही सहकारिता से जुड़े समाज को ऊर्जा से भर देगा और जो सोये हैं अभी तक उन्हें जगाकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा।

अमित शाह ने 'सहकार एवं रोजगार उत्सव' में युवाओं से कहा कि मोदी सरकार ने 11 साल के कार्यकाल में 60 करोड़ गरीबों के लिए घर, शौचालय, बिजली, गैस, पांच किलो मुफ्त अनाज और पांच लाख रुपये तक के इलाज और मुफ्त दवाइयों की व्यवस्था की। हर गांव, गरीब और किसान तक सहकारिता को पहुंचाने के लक्ष्य के साथ केन्द्र सरकार में एक स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय स्थापित किया। आज 98 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में सहकारिता की सक्रिय भूमिका है। आगामी 100 साल सहकारिता के होंगे। अतीत के सहकारिता के आन्दोलनों से अब तक के आकलन के साथ गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय सहकारिता की पहुंच को रेखांकित किया कि देश के धान और गेहूं की खरीद में लगभग 20 प्रतिशत योगदान सहकारिता का है, जबकि 35 प्रतिशत उर्वरक और 30 प्रतिशत चीनी का उत्पादन सहकारिता के माध्यम से होता है। 20 प्रतिशत से ज्यादा उचित मूल्य की दुकानें-फेयर प्राइस शॉप भी सहकारिता के माध्यम से चलती हैं। 8 लाख 50 हजार सहकारी संस्थाओं के माध्यम से 31 करोड़ लोग सहकारिता से जुड़े हैं। यह जो करोड़ों भारतीयों का सहकारिता से जुड़ाव है, यह बहुत मायने रखता है। चार वर्ष में ही भारत की इतनी बड़ी आबादी सहकारिता में अपनी उपस्थिति बना चुकी है। यह आगामी 100 साल बाद का जो उन्हें चित्र दिख रहा है, वह यूं ही नहीं है। यह उन्हें आभास इसलिए हो रहा है क्योंकि सहकारिता भारतीय जीवन पद्धति, जीवन समृद्धि व उत्साहजनक भविष्य की कड़ी बनती जा रही है। उन्होंने खुद देखा कि विज्ञान व तकनीकी के साथ जैसे सहकारिता का जुड़ाव हो रहा है, युवा आबादी इसमें अपने भविष्य को संवारने का स्वप्न पाल रही है। वह अपने बुजुर्गों की विरासत में सम्मिलित सहकारिता को आगे बढ़ाना चाहती है।

प्राइमरी डेयरी कोआपरेटिव सोसाइटी-पीडीसीएस ऑनलाइन पंजीकरण प्लेटफॉर्म का शुभारंभ हुआ और पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम अभियान के तहत सफलता की कहानियां जब सामने आयीं तो लोगों ने महसूस किया है कि सहकारिता भी सफलता की वजह बनती जा रही है। वन्दे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत सफलता की कहानियों ने यह बताया कि हमारी सहकारिता केवल कृषि व उद्यम तक सीमित नहीं है अपितु यह तो प्रकृति-जीवन-संस्कृति से जुड़ी हुई है। सहकारिता मंत्री ने रेखांकित किया है कि सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के चार वर्ष के भीतर हमने 61 पहलों के जरिये सहकारिता को मजबूत करने का काम किया है। दो लाख नए पीएसीएस बनाने का काम शुरू हो गया है, इनमें से 40 हजार पैक्स बना लिए गए हैं। सभी पीएसीएस -पैक्स के कम्प्यूटरीकरण का काम पूरा कर लिया गया है और सभी राज्यों ने पैक्स के मॉडल

बायलॉज स्वीकार कर लिए हैं। गोदाम भी बनाए जा रहे हैं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, एक्सपोर्ट और बीज संवर्धन के लिए नई सहकारी संस्थाएं बनाई गई हैं। यदि यह कार्य व ऐसा कार्य जो सहकारिता मंत्रालय गठन के बाद विगत चार वर्षों में सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया है, ऐसा कार्य पिछले 75 वर्षों में किया गया होता तो, आज देश में सहकारिता की वजह से हमारे देश के किसान, मजदूर, श्रमिक व विभिन्न हितधारक भारत का भविष्य बदलने में सक्षम हो चुके होते, किसी अन्य सहयोग की अपेक्षा ही नहीं होती। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, नए अनुबंध-एमओयू, मानव संसाधन का निर्माण, नए रिसोर्सेज का चिन्हीकरण व उनको डिजिटल फॉर्म में सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया भी सहकारिता क्षेत्र में हो रही है। क्लाइमेट चेंज व सोशल जस्टिस जैसे विषयों को भी सहकारिता के समावेशी वैशिष्टय के साथ समाधान होगा। आत्मनिर्भरता व नवाचार से आर्थिक विकास की धारा जेंडर जस्टिस का कारण बनेंगी। भारत में सहकारी समितियों की जिस प्रकार बढ़ोतरी हो रही है, उनके प्रति उदासीनता को समाप्त करके इसे अभिरुचिजन्य बनाने की यदि कोशिश नया स्वरूप पाएगी तो 2047 तक विकसित राष्ट्र के पैमाने पर भारत 100 प्रतिशत खरा उतरेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। सबसे अहम बात यह है कि सहकारिता मंत्री का युवा मन युवा सहकारिता सेवियों को जब तैयार कर लेगा, तो कोई लक्ष्य हमसे दूर नहीं होगा। अपने युवा मानव संसाधन का बस तेजी से झुकाव सुनिश्चित करने में यदि भारत सरकार अभिरुचि दिखाएगी तो सब कुछ संभव सा होता दिखता है। सहकारिता मंत्री की ओर से की जा रही पहल के साथ जब वैश्विक स्तर पर इन्वेस्टमेंट करने वाली एजेंसीज सहकारिता से जुड़े लोगों व प्रतिष्ठानों के बीमा में अभिवृद्धि करेंगी और सुरक्षा की भावना से वे अभिरुचि दिखाकर आगे आने का प्रयत्न करेंगी तो निश्चय ही सहकारिता के 100 वर्ष और 500 वर्ष भी स्वर्णिम काल में परिवर्तित हो सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट एजेंसीज की इच्छाशक्ति का अहम योगदान है।

वे ऐसा करेंगी तो आने वाले समय में विभिन्न चुनौतियों के बीच भी सहकारिता के कार्य आगे बढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि सहकारी समितियां ऐसे स्वैच्छिक आर्थिक संगठन होते हैं, जहाँ सदस्य मिलकर कोई कामकाज करते हैं, जिसमें आर्थिक नुक़सान या अस्थिरता का कुछ जोखिम भी हो सकता है, और उसके ज़रिए आय अर्जित करते हैं। ये संस्थाएँ न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक रूप से भी लोगों को सशक्त बनाती हैं। यह कार्य भारत में मद्धिम था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की पहल से बने नए मंत्रालय व अमित शाह के नेतृत्व के कारण इसे बल मिला। भारत में इस समय लगभग 8 लाख सहकारी संस्थाएं हैं जिनके ज़रिए आर्थिक विकास और लोगों के सशक्तीकरण में सहयोग मिल रहा है, यह कोई मामूली बात नहीं है। जब देश में सहकारी संस्थाओं की संख्या 8 करोड़ हो जाएगी, जब देश में सहकारी संस्थाओं का पूर्णतया डिजिटलीकरण हो जाएगा, जब देश में त्रिभुवन यूनीवर्सिटी जैसी सहकारिता यूनिवर्सिटी की संख्या बढ़कर कम से कम 10 हो जाएगी, जब देश में सहकारिता अनुसंधान में सतत विकास हमें दिखेगा तो संपूर्ण विश्व में भारत का सहकारिता आन्दोलन अपने वैभवकाल की ओर गति पा लेगा, हमारे देश को एक ऐसे समय की प्रतीक्षा है। सहकारिता मंत्री अमित शाह को भी ऐसा समय प्राप्त कर लेने का विश्वास है। आवश्यकता इस बात की है कि उस विश्वास को पूरा भारत मजबूती से अपना सहयोग प्रदान करे, क्योंकि इसमें किसी के निहित स्वार्थ नहीं हैं, अपितु इसमें पूरे भारत का भविष्य है। आज 24 जुलाई को राष्ट्रीय सहकारिता नीति सरकार ला रही है।

(लेखक केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब में वेयर प्रोफेसर हैं, ये उनके अपने विचार हैं।
लेख पर अपनी प्रतिक्रिया edit@haribhoomi.com पर दे सकते हैं।

Downloaded from
SAMVAD

Publication	**Greater Kashmir**	**Language**	English
Edition	Srinagar	**Journalist**	
Date	24/07/2025	**Page no**	9
CCM	N/A		

India marks UN International Year of Cooperatives 2025 with nationwide campaign

India marks UN International Year of Cooperatives 2025 with nationwide campaign

GK News Service
New Delhi, Jul 23

India is observing the United Nations' International Year of Cooperatives (IYC) 2025 with a nationwide campaign themed "Cooperatives Build a Better World." The Ministry of Cooperation has launched a series of initiatives to highlight the sector's role in inclusive and sustainable development. A national action plan was unveiled in January by Union Home and Cooperation Minister Amit Shah, with events coordinated through central and state-level committees. The IYC logo has been widely promoted on railway tickets, government websites, Amul milk packets, and during the Women's Premier League.

Key highlights include the foundation stone of India's first cooperative university in Gujarat, a national conference of cooperation ministers in New Delhi, and the launch of 25 PACS godowns in Bihar. A special plantation drive under the "Ek Ped Maa Ke Naam" campaign is underway across over 25 States and UTs.

Jammu & Kashmir hosted awareness camps, retail inaugurations, and yoga events, while Ladakh held training workshops, seminars, and distributed dairy equipment to local farmers. The Ministry is also working on benchmarking standards and a Business Reform Action Plan for cooperatives, with a consolidated national report to be released at the end of the year.

Downloaded from
SAMVAD

Publication	**Central Chronicle**	**Language**	English
Edition	Bhopal	**Journalist**	
Date	24/07/2025	**Page no**	1
CCM	N/A		

Shah to unveil National Cooperative Policy 2025 today

Shah to unveil National Cooperative Policy 2025 today

New Delhi (UNI)

Union Home Minister and Minister of Cooperative Amit Shah will announce the National Cooperative Policy 2025 here on Thursday.

The new cooperative policy will prove to be a milestone in the cooperative movement of India for the next two decades from 2025-45, an official statement said here today.

The new cooperative policy 2025 aims to revive and modernise the cooperative sector as well as realise the vision of prosperity through cooperation by creating a roadmap at the grassroots level.

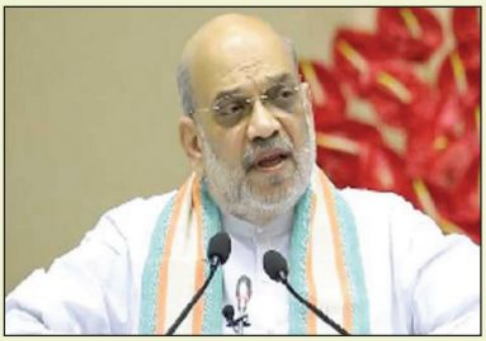

In 2002, the country's first National Cooperative Policy was issued, which gave a basic framework for better management of the economic activities of cooperative institutions. In the last 20 years, many major changes have taken place in the society, country and the world due to globalization and technological advancement. Keeping these changes in mind, it became necessary to formulate a new policy, so that cooperative institutions can be made more active and useful in the current economic scenario and the role of the cooperative sector can be strengthened in achieving the goal of "Viksit Bharat 2047".

Downloaded from SAMVAD